इकाई 7 जाति और वर्ग*

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 प्रस्तावना
7.2 वर्ण और जाति
7.2.1 जाति प्रणाली और विशेषताएं
7.2.2 जाति की प्रकृति
7.3 भारत में सामाजिक वर्ग
7.3.1 भारत के वर्ग निर्माण में ब्रिटिश शासन का प्रभाव
7.3.2 भारत में सामाजिक वर्गों का विकास
7.3.3 ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग
7.3.4 शहरी भारत में सामाजिक वर्ग
7.4 जाति और वर्गों के बीच संबंध
7.5 सारांश
7.6 संदर्भ
7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समर्थ होंगें:

- एक संस्था के रूप में जाति और वर्ग को परिभाषित कर सकेगें;
- संस्कृति की अवधारणा के माध्यम से जाति व्यवस्था में जाति की गातिशीलता का विश्लेषण कर सकेंगे;
- ग्रामीण और शहरी भारत के वर्गों और इसके असमान विकास पर विस्तार से चर्चा कर सकेंगे; और
- जाति और वर्ग के बीच संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

जाति को लंबे समय से भारतीय समाज की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। यह केवल एक संस्था नहीं है जो भारत में सामाजिक स्तरीकरण की संरचना की विशेषता हैं। ''जाति'' को अक्सर भारत की मूल व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए देखा गया है। इसे एक संस्था के साथ-साथ एक विचारधारा के रूप में भी देखा गया है। संस्थागत रूप से, ''जाति'' ने सामाजिक समूहों को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में उनकी स्थिति के संदर्भ में व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इसने व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम की सरंचना में तय किया है। एक विचारधारा के रूप में, जाति उन मूल्यों और विचारों की एक प्रणाली है जो सामाजिक

*प्रो. रवीन्द्र कुमार, समाजशास्त्र संकाय, इग्नू द्वारा इकाई 20 और 23 ESO-12 से अनुकूलित।

असमानता की मौजूदा सरंचना को वैध और सुदृढ़ करती है। इसने एक विश्वदृष्टि भी प्रदान की जिसके चारों और एक विशिष्ट हिन्दू अपने जीवन को व्यवस्थित करता है।

एक ऐसी संस्था होने के अलावा जो भारत को अन्य समाजों से अलग करती हैं, जाति पारंपरिक समाज का एक प्रतीक भी था, एक ''बंद प्रणाली'', जहां पीढ़ी दर पीढ़ी के व्यक्ति एक ही तरह के काम करते हैं और कमोबेश इसी तरह के जीवन जीते हैं। इसके विपरीत, पश्चिम के आधुनिक औद्योगिक समाजों को सामाजिक स्तरीकरण की ''खुली प्रणाली'' को माना गया है, जो समाज वर्ग पर आधारित थें, जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं और इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। धन, आय, शिक्षा, व्यवसाय वर्ग के कुछ मूल निर्धारक हैं। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए काम करता है, तो स्तरीकरण की एक खुली प्रणालियों में, वे सामाजिक पदानुक्रम में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी वर्ग स्थिति बदल सकते हैं। जाति व्यवस्था में व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी गतिशीलता असंभव थी। जाति को सामाजिक स्तरीकरण के एक चरम रूप में देखा गया हैं।

7.2 वर्ण और जाति

सिद्धांत रूप में, जाति व्यवस्था ''वर्ण'' के आदर्श से जुड़ी हुई है जो हिंदू समाज को चार व्यवस्थाओं में विभाजित करती है, जैसे, ब्राह्मण, (ब्राह्मण, पारंपरिक रूप से, पुजारी और विद्वान), क्षत्रिय (शासक और सैनिक), वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (किसान, मजदूर और नौकर)। पहली तीन जातियां-'दो बार जन्मी' या 'द्विज' हैं क्योंकि इन जातियों के पुरूष उपनयन के वैदिक अनुष्ठान में पवित्र होने के हकदार हैं जो शूद्रों को करने की अनुमति नहीं थी। अछूत जातियां वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं।

शब्द 'वर्ण' का शाब्दिक अर्थ रंग है और इसे मूल रूप से प्राचीन भारत में आर्य और दास के बीच के अंतर को संबोधित करने के उपयोग किया जाता था। (घुरिये 1950:52)

जाति व्यवस्था एक अखिल भारतीय घटना हैं, जिसे वर्ण आदर्श एक अखिल भारतीय वृहत सरंचनात्मक योजना प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, वर्ण व्यवस्था केवल एक रूपरेखा प्रदान करता हैं जिसके भीतर पूरे भारत में जातियों की असंख्य विविधताएँ पाई जाती हैं। श्रीनिवास (1962:65) के अनुसार शब्द की शाब्दिक अर्थ में वर्ण-साहित्यिक योजना एक 'पदानुक्रम' हैं क्योंकि कर्मकाण्डीय शुद्वता और प्रदूषण के मानदंड इस भेदभाव के आधार पर हैं। सामान्यतया, उच्च जातियां सम्पन्न जातिया हैं, और निचली जातियां आम तौर पर निम्र वर्ग हैं। हालांकि, जाति और वर्ग के बीच का यह जुड़ाव हमेशा सच नहीं होता है। स्थानीय जाति पदानुक्रम में एक जाति अनुष्ठानिक रूप से उच्च लेकिन निम्र स्थान पर हो सकती है क्योंकि यह पदानुक्रम आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक स्थिति जैसे धर्मनिरपेक्ष कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, जाति व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक, वास्तविक सच्चाई के रूप में, पदानुक्रम में अस्पष्टता रही हैं, खासकर मध्य पायदान में।

वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की केवल चार श्रेणियां हैं। यह व्यवस्था उन अछूतों को शामिल नहीं करती है जो पूरे भारत में समान हैं। लेकिन यह वास्तविकता में सही नहीं है क्योंकि वैदिक काल के दौरान भी, व्यावसायिक समूहों का अस्तित्व था, जिन्हें वर्ण नहीं माना जाता था, हांलाकि कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि इन समूहों को जाति कहा जा सकता है या नहीं। घुरिये के अनुसार, प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में, लगभग 200 जाति समूह होते हैं जो आगे उप-विभाजित होते हैं, जो लगभग 3000 छोटी इकाइयों में विभाजित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अन्तर्विवाही होता है और व्यक्ति के लिए प्रभावी सामाजिक जीवन का

क्षेत्र प्रदान करता है। इसलिए, कोई यह कह सकता है कि वर्ण व्यवस्था समाज की व्यापक श्रेणियों को सबसे अधिक संदर्भित करती (श्रीनिवास 1962:65)। चित्र से पता चलता है कि एक वर्ण में विभिन्न जातियाँ शामिल हो सकती हैं और इन जातियों को अलग-अलग उपजातियों में विभाजित किया जा सकता हैं।

7.2.1 जाति व्यवस्था की विशेषताएं

जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं:

i) पदानुक्रम

ii) सगोत्र विवाह, अर्न्तविवाह

iii) एक वंशानुगत व्यवसाय

iv) भोजन और सामाजिक संबंधो पर प्रतिबंध,

v) रिवाज, पहनावा और बोली में अंतर और

vi) समाज में विभिन्न जाति समूहों द्वारा प्राप्त नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, (घुरिये 1950:50)।

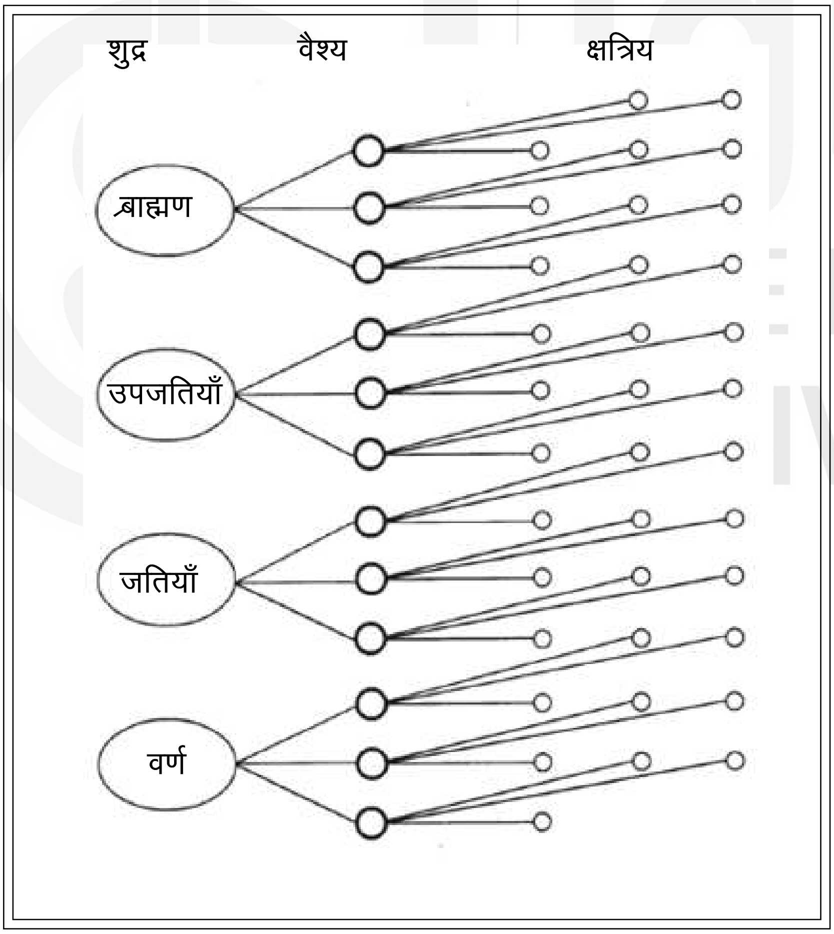

हिन्दू समाज जाति के खंडीय विभाजन में बंटा हुआ हैं। जाति एक प्रदत्त स्थिति है। जातिगत समाज में, अछूतों को अशुद्व माना जाता हैं। इस प्रकार, पदानुक्रम की अवधारणा जाति समाज का सार बनाती है। प्रत्येक जाति कर्मकाण्ड के अर्थों में अन्य की तुलना में अधिक शुद्व या अशुद्व मानी जाती हैं। कुछ जातियों की छाया भी अशुद्व माना जाता था।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, शानर या ताड़ी निकालने वाले को ब्राह्मणों से चौबीस कदम दूर रहना था। केरल में, एक नायर एक नंबुदिरी ब्राह्मण से संपर्क कर सकता था लेकिन उसे छू नहीं सकता था, और तियान जाति एक सदस्य खुद को एक ब्राह्मण से 36 कदम की दूरी पर रखता था (घुरिये 1950)। इसलिए परंपरागत रूप से अछूत मानी जाने वाली जातियों को उच्च-जाति के घरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दक्षिण भारत में, यहाँ तक कि ब्रिटिश काल तक, शहर और शहरों के कुछ हिस्से अछूत जातियों के लिए प्रतिबंधित थे।

अन्तर्विवाह या किसी एक जाति या उपजाति समूह के भीतर विवाह जाति व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता हैं। यह जाति व्यवस्था की दृढ़ता के मुख्य कारणों में से एक हैं। लोग आमतौर पर एक ही जाति समूह में विवाह करते हैं।

परंपरागत रूप से, प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। ग्रामीण भारत में प्रचलित पाई जाने वाली जजमानी प्रणाली ने प्रत्येक जाति को अपने वंशानुगत व्यवसाय पर एकाधिकार पाने में सक्षम बनाया। प्रत्येक जाति को उनके संबंधित व्यवसायों की कर्मकाण्डीय शुद्वता या अशुद्वता के आधार पर उच्च या निम्न स्थान दिया गया था। इस प्रकार, उत्तर भारत की चमान जातियों को अछूत माना जाता था क्योंकि उनके पेशे में चमड़े का उपयोग संबंधित था।

प्रत्येक जाति की अपनी जाति परिषद या पंचायत होती थी जहाँ उसकी जाति के सदस्यों की शिकायतों को सुना जाता था। इन जाति-परिषदों की अगुवाई, आम तौर पर उस जाति के बड़े सदस्यों द्वारा की जाती थी, अगर वे जाति प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करते थे, तो उनकी जाति से एक सदस्य को बहिष्कृत करने की शक्ति थी। जाति प्रतिबंध विवाह, सहभोग या अंतर-भोजन और सामान्य सामाजिक संपर्क में भी संचालित होते हैं।

बोध प्रश्न 1

i) जाति की अवधारणा को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें।

....

....

....

....

....

....

....

ii) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरें।

a) जाति की स्थिति एक .... स्थिति हैं।

b) कर्मकाण्ड .... और .... जाति के पदानुक्रम में एक जाति का स्थान निर्धारित करता है।

c) शब्द .... का शाब्दिक अर्थ है रंग।

d) वर्ण एक अखिल भारतीय श्रेणी है जबकि .... एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता हैं।

7.2.1 जाति व्यवस्था के लक्षण

जाति व्यवस्था की उपरोक्त प्रस्तुति को पदानुक्रम के सभी समावेशी सिद्वांत पर आधारित एक बंद प्रणाली के रूप में है जो अपने सदस्यों के लिए गतिशीलता की अनुमति नहीं देती हैं, सभी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हैं। कुछ समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानववैज्ञानिकों ने आपत्ति उठाई है और इस तरह की अवधारणा की बहुमूल्य आलोचना की है। एम एन श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा द्वारा की गयी आलोचना सबसे उल्लेखनीय हैं।

संस्कृतिकरण

एम.एन.श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था की गतिशील प्रकृति का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को इन शब्दों में परिभाषित किया हैं, ''एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक 'निम्न' हिन्दू जाति, या आदिवासी या अन्य समूह, एक उच्च, अक्सर, द्विज जाति की दिशा में अपने रीति-रिवातों, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन के तरीके को बदल देता हैं। आम तौर पर इस तरह के बदलावों द्वारा जाति पदानुक्रम में एक उच्च पद के लिए दावा किया जाता है, जो परंपरागत रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा दावेदार जाति को स्वीकार किया जाता हैं। ''यह संस्कृतिकरण की बहुत व्यापक परिभाषा है। यह न तो केवल संदर्भ समूह के रूप में ब्राह्मणों तक सीमित है और न ही विचारधाराओं की नकल करने के लिए।

उनका अवलोकन, जाति व्यवस्था में गतिशीलता या बदलाव की विविधता और बदलाव की ओर इशारा करता हैं। अपने अवलोकन को अधिक शाक्तिशाली और अनुभविक रूप से प्रमाणित करने के लिए, वह के.एम. पणिक्कर के ऐतिहासिक अध्ययन का हवाला देता हैं। पाणिवकर जा मानते हैं कि सभी क्षत्रिय निचली जातियों द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करके और क्षत्रिय भूमिका और सामाजिक स्थिति के कारण अस्तित्व में आए हैं।

श्रीनिवास आगे कहते हैं कि हालांकि सभी गैर प्रमुख, विशेष रूप से निम्न या गैर-द्विज जातियां खुद का संस्कृतिकरण करना चाहती हैं, लेकिन केवल वे ही सफल होते हैं जिनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में सुधार हुआ हैं।

7.3 भारत में सामाजिक वर्ग

सामाजिक वर्ग को एक प्रकार के सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया हैं, जो न तो कानूनी रूप से परिभाषित है और न ही धार्मिक रूप से स्वीकृत है। यह आमतौर पर समान सामाजिक पदों पर बैठे लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया हैं। धन, आय, शिक्षा, व्यवसाय वर्ग के कुछ मूल निर्धारक हैं। यह अपेक्षाकृत खुला हैं, यानी कोई भी जो बुनियादी मानंदडों को पूरा करता हैं, वह इसका सदस्य बन सकता हैं। एक समाज में कई वर्ग होते हैं। इन वर्गों को मुख्य रूप से धन और आय के मामले में श्रेणीबद्ध किया गया हैं। धन और आय के अंतर को विभिन्न जीवन शैलियों और उपभोग पद्धति में व्यक्त किया जाता है। सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं (बॉटमोर 1962'188)। आपकों एक उदाहरण देने के लिए, एक पूंजीवादी समाज में हम आम तौर पर कई अन्य लोगों के अलावा पूंजीपतियों के वर्ग और मजदूर वर्ग को पाते हैं।

भारत में सामाजिक वर्ग, जैसा कि हम आज उन्हें देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी उत्पत्ति हुई। यह नहीं कहा जा सकता हैं कि वर्ग की घटना ब्रिटिश-पूर्व भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। भारतीय समाज का वर्ग आयाम ब्रिटिश काल के दौरान होने की तुलना में

कम स्पष्ट था। ग्राम समुदाय की तथाकथित आत्मनिर्भरता इसक पीछे एक कारण प्रतीत होता हैं। दूसरे शब्दों में, गाँव समुदाय आम तौर पर केवल वही उत्पादित करता है जो गाँव की उपभोग की जरूरतों के लिए आवश्यक था। इसलिए गाँव की आबादी के बीच बहुत कम आधिक्य था और इसलिए कम अंतर था।

यहाँ तक कि जब एक वर्ग आयाम को चिन्हित किया गया था; उसे जातिगत घटकों ने ढक लिया। वास्तक में, एकमात्र क्षेत्र जहां वर्ग आयाम ने खुद को और अधिक तेजी से दिखाया, शासकों और शासितों के बीच बातचीत की प्रकृति में था। राजा और उनके दरबारियों ने उन लोगों से काफी अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, जिन पर उन्होंने शासन किया था। दरबारियों में जमींदार, जागीरदार और कई अन्य लोग शामिल थे। वे राजा के साथ ग्राम समुदाय से प्राप्त राजस्व पर निर्भर अपने अधिकार क्षेत्र में रहते थे।

इन वर्गों के अलावा व्यापारियों, कारीगरों और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों के विभिन्न क्रमों के प्रशासनिक अधिकारियों के वर्ग भी थे।

भारत में औपनिवेशिक शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने नए तत्वों को पेश किया, जिसके कारण भारतीय समाज में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब देखते हैं कि भारत में वर्ग निर्माण पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव था।

7.3.1 भारत में वर्ग निर्माण पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव

भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव ने भारतीय समाज में दूरगामी परिवर्तन लाए हैं। इनमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई हैं।

1) कृषि में परिवर्तन

   अंग्रेजों ने अठारहवीं शताब्दी के दौरान कई भूमि सुधारों को लागू करके भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार बनाए, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैय्यतवारी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त। इस तरह, भूमि निजी संपत्ति और बाजार की एक वस्तु बन गई, जिसे गिरवी रखा जा सकता हैं, खरीदा या बेचा जा सकता है। भू-राजस्व तय करने की एक नई विधि और उसके नकद भुगतान की शुरूआत की गई थी। कृषि के इस व्यावसायीकरण ने, भारत में व्यापार और वाणिज्य के विकास को प्रेरित किया।

2) व्यापार और वाणिज्य

   व्यापार और वाणिज्य दो चीजों के आसपास केंद्रित थेः इस सबका उत्तरार्द्ध का हस्तशिल्प के आधार पर कस्बों और गाँवों की स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

   क) ब्रिटेन में उद्योगें के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और

   ख) भारत में खपत के लिए ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की खरीद।

3) रेलवे और उद्योग का विकास

   व्यापार और वाणिज्य की वृद्वि के साथ, भारत में परिवहन प्रणाली का तेजी से विकास हुआ। रेलवे का विस्तार उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से बढ़ते पैमाने पर हुआ। ये विकास ब्रिटेन में उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए थे। रेलवे और सड़कों के निर्माण ने भी भारत में ब्रिटिश पूंजी के निवेश की गुंजाइश दी। इसने सैनिकों की बेहतर गतिशीलता और कानून और व्यवस्था की

स्थापना के लिए सहयोग किया। तब तक, भारतीय व्यापारियों और व्यापारियों की ओर से पर्याप्त बचत का संचय किया गया था। इसने पूंजी के रूप में कार्य किया और भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों के निर्माण को संभव बनाया।

4) राज्य और प्रशासनिक प्रणाली

इन प्रक्रियाओं से पहले भी, ब्रिटिश सरकार ने विजय प्राप्त करने के लिए एक विशाल और व्यापक राज्य तंत्र का संगठन किया था। इस मशीनरी को बनाने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी चलाने के लिए ब्रिटेन के शिक्षित लोगों के कर्मचारियों को लाना संभव नहीं था। इसलिए विदेशी शासकों को लगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरूआत की आवश्यकता है। इस प्रकार, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने और बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती राज्य मशीनरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के परिणामस्वरूप, भारतीय समाज ने सामाजिक वर्गों के असमान विकास को देखा। हम अगले भाग में इस असमान विकास के कुछ पहलुओं की जांच करने जा रहे हैं।

बोध प्रश्न 2

i) सामाजिक वर्ग की अवधारणा को परिभाषित करें।

....

....

....

....

....

ii) भारत में सामाजिक वर्गों के उद्भव के लिए कुछ बदलावों की सूची बनाएं।

....

....

....

....

....

....

iii) सामाजिक वर्ग के असमान विकास को दर्शाने वाले दो क्षेत्र बताइए। लगभग दो पंक्तियों का उपयोग करें।

....

....

....

....

....

....

7.3.2 भारत में सामाजिक वर्गों का विकास

भारत में सामाजिक वर्ग, जैसा कि हम आज उन्हें देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी उत्पत्ति हुई। यह नहीं कहा जा कसता है कि वर्ग की परिघटना ब्रिटिश पूर्व भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। भारतीय समाज का वर्ग आयाम ब्रिटिश काल के दौरान होने की तुलना में कम स्पष्ट था। नए सामाजिक वर्गों के उदय की प्रक्रिया असमान थी। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में और विभिन्न समुदायों के बीच समान रूप से विकास नहीं किया। इस तथ्य के कारण था कि सामाजिक ताकतें, जो ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुईं, समय और गति दोनों में असमान रूप से फैल गईं। यह बदलें में, भारत में राजनीतिक शक्ति के विकास पर निर्भर था। उदाहरण के लिए, बंगाल में दो सामाजिक वर्ग - जमींदार और कृषक - पहले अस्तित्व में आए। पुनः बंगाल और बंबई औद्योगिक उद्यम शुरू हुए। इससे इस क्षेत्र में उद्योगपतियों और श्रमिकों के वर्ग का उदय हुआ। यह इस कारण से था कि अंग्रेजो ने एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और बंगाल और बंबई में आधुनिक शिक्षा की शुरूआत की।

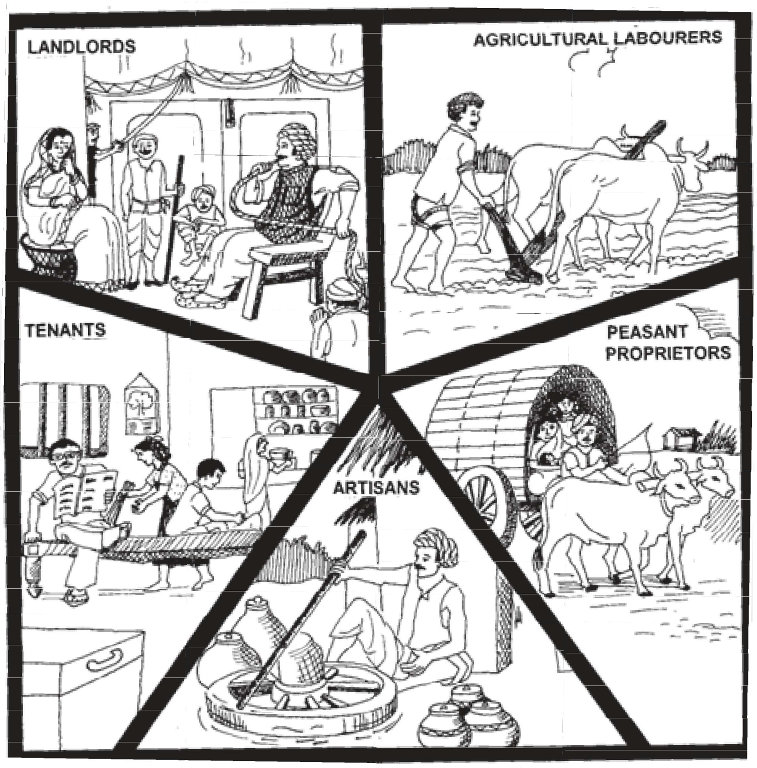

विभिन्न समुदायों के बीच नए सामाजिक वर्गों के उदय की प्रक्रिया भी असमान थी। यह इस तथ्य के कारण था कि कुछ समुदाय पहले से ही ब्रिटिश काल में निश्चित आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक व्यवसाय में लगे हुए थे। उदाहरण के लिए हमारे पारंपरिक सामाजिक सरंचना में व्यवसाय द्वारा बनिया व्यापारी थे। इसलिए वे आधुनिक वाणिज्य, बैंकिग और औद्योगिक उद्यमों को विकसित करने वाले पहले थे (मिश्रा 1978:14)। इसी तरह, ब्राह्मण आधुनिक शिक्षा लेने और पेशेवर कक्षाओं में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन समुदायों ने नई चुनौतियों को उठाया और गतिविधि के इन क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश किया क्योंकि वे पहले से ही इन व्यवसायों के लिए मूल स्वाभाव रखते थे।

7.3.3 ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः (क) जमींदार, (ख) मालिक किसान, (ग) कृषक, (घ) खेतीहर मजदूर और (च) कारीगर रहते हैं।

क) जमींदार

1950 के दशक में आजादी के बाद भूमि सुधार के उपाय खेती करने वालों का एक सामाजिक रूप से सजातीय वर्ग बनाने में विफल रहे। कृषि पदानुक्रम के शीर्ष स्तर पर बैठे जमींदारों ने किसानों से कर निकालने के अपने अधिकार को खो दिया। उन्हें छोटे भूमि के स्वामित्व के साथ छोड़ दिया गया था। उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व भी टूट गया था। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा किराये पर रहने वालों के रूप में रहता हैं। बाकी ने अपने खेत के प्रबंधन और सुधार मे सक्रिय भागीदारी की हैं।

ख) मालिक किसान

मलिक किसान को मुख्यतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं,

i) अमीर किसानः वे बहुत बड़े भूमि के मालिक होते हैं। वे क्षेत्र मे कोई कार्य नहीं करते हैं लेकिन खेती की निगरानी करते हैं और भूमि प्रबंधन और सुधार में व्यक्तिगत रूचि लेते हैं।

ii) मध्य किसानः वे मध्यम आकार के जोत के भूस्वामी हैं। वे आम तौर पर आत्मनिर्भर होते हैं। वे पारिवारिक श्रम के साथ भूमि पर खेती करते हैं।

iii) गरीब किसानः वे छोटे भूमि के स्वामी होते हैं जो एक परिवार को पालने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। उन्हें मजदूरों के रूप में दूसरों के भूमि पर काम करना पड़ता है और किराये की भूमि पर भी खेती करती पड़ती है। वे कृषि आबादी के एक बड़े हिस्से का गठन करते हैं।

ग) कृषक

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, किरायेदारों की विभिन्न श्रेणियां थी। मोटे तौर पर उन्हें किरायेदारों, उप-सहायक, बटाईदार आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैं,

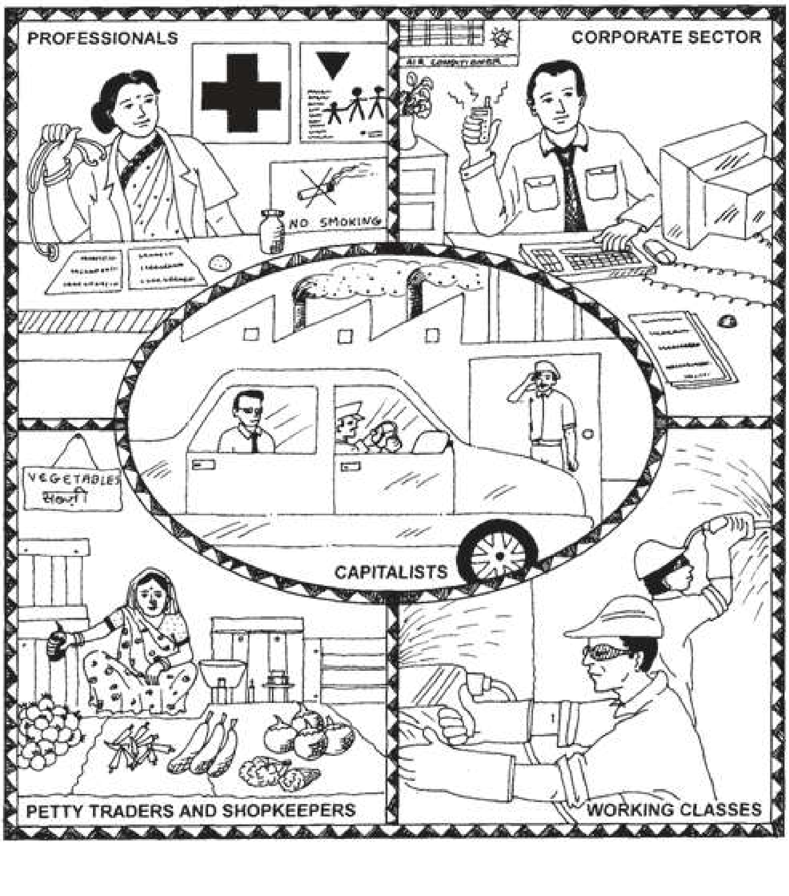

जमींदारी क्षेत्रों में, जातहर हैं, ज़मींदारों और वास्वविक कृषक के बीच कई उप-श्रेणियां थी जो सामान्य बटाईदार मे थीं। पूरी तरह से किरायेदारों ने अधिकार प्राप्त किया। उन्हें निकाला नहीं जा सका। सामान्य तौर पर उप-किरायेदारों ने कार्यकाल की कुछ सुरक्षा का आनंद लिया, लेकिन बेदखली के लिए उत्तरदायी थे। दूसरी ओर बटाईदारों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी और वे किरायेदारों के संपन्न वर्ग की दया पर थे और किरायेदारों की किरायेदारी सुधार कार्यक्रम के साथ किसान मालिकों में बदल दिया गया था। दूसरी ओर बटाईदारों को इन कार्यक्रमों से कम लाभ हुआ। भूमि सुधार के दूसरे चरण के में, भूमि स्वामित्व की सीमा और किरायेदारी की सीमा में कमी हुई हालाँकि, इसके बाद भी बटाई करना जारी है। वास्तव में, यदि ग्रामीण भारत में केवल किरायेदार वर्ग नहीं हैं, तो बटाईदार सबसे महत्वपूर्ण हैं। संगठन और राजनीतिक रूप से, वे कमजोर हैं, हालांकि वे भारत में किसान संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं।

घ) खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूर तीन प्रकार के थे। कुछ लोगों के पास अपने श्रम की बिक्री से अपनी आजीविका चलाने के अलावा जमीन का एक छोटा सा भूंखड था। अन्य भूमिहीन थे और अपने श्रम की बिक्री पर ही निर्भर थे। अपने श्रम के बदले में, खेतिहर मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी, जो बहुत कम थी। उनके रहने की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। आम तौर पर मजदूरी का भुगतान धान के रूप में किया जाता था यानी धान, गेहूं और दालों की तरह। कभी-कभी नकद का भुगतान मजदूरी के बदले किया जाता था। इन मजदूरी को देने के लिए एक निश्चित मानक उपाय को नियोजित किया गया था। वास्तव में, पैसे के भुगतान के साथ-साथ वस्तुओं का भुगतान भी जारी रहा। एक ओर बंधुआ मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी संरचना को समाप्त करने की दिशा में विधान, और दूसरी ओर रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस वर्ग के लिए सरकार की चिंता को दर्शाते हैं। इस तरह के उपाय, हालांकि, बहुत कारगर नहीं हैं। खेतिहर मजदूर ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर तबके का गठन करते हैं।

च) कारीगर

ग्रामीण भारत के कारीगरों में बढ़ई, लोहार, कुम्हार इत्यादि को शामिल किया जाता है। सभी गाँवों में इन कारीगरों के परिवार नहीं थें, लेकिन जजमानी प्राणाली के तहत, कभी कभी इन व्यावसायिक जातियों के एक परिवार ने एक से अधिक गाँवों में सेवा की। ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को ब्रिटिश शासन के तहत कड़ी टक्कर मिली क्योंकि वे मशीन निर्मित और सस्ते औद्योगिक सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे।

7.3.4 शहरी भारत में सामाजिक वर्ग

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वर्गों में मुख्यतः (क) पूँजीपति (वाणिज्यिक और औद्योगिक), (ख) व्यवसायिक (Corporate) क्षेत्र (ग) पेशेवर वर्ग, (घ) छोटे व्यापारी और दुकानदार और (च) श्रमिक वर्ग शामिल हैं।

क) पूँजीपति (वाणिज्यिक और औद्योगिक) वर्ग

ब्रिटिश काल के दौरान, भारत में उत्पादन मुख्यतः बाजार के लिए होता था। इसके परिणामस्वरूप, आंतरिक बाजार का विस्तार हुआ और आंतरिक व्यापार में लगे

व्यापारियों का वर्ग बढ़ा। इसके साथ ही भारत को विश्व बाजार से भी जोड़ा गया। इससे निर्यात-आयात व्यवसाय में लगे व्यापारियों के एक वर्ग का विकास हुआ। इस प्रकार, देश में एक वाणिज्यिक मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया।

ख) व्यवसायिक (Corporate) क्षेत्र

कोई भी संगठन जो सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ कहा जाता हैं और कोई भी संगठन, जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबधित नहीं हैं, को निजी क्षेत्र का हिस्सा होता हैं। निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से स्वामित्व और नियंत्रित और प्रबंधित की जाने वाली फर्म और संगठन निजी क्षेत्र में शामिल हैं। सभी निजी क्षेत्र की फर्मों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व।

सामूहिक स्वामित्व वाली फर्मों को आगे i) साझेदारी फर्मों ii) संयुक्त हिंदू परिवार iii) संयुक्त स्टॉक कंपनियों और iv) सहकारी समितियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त स्टॉक संगठन हैं, जो अन्यथा कॉपोरेट क्षेत्र के रूप में लोकप्रिय हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनियां जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबधित नहीं हैं, उन्हें सामूहिक रूप से निजी कारॅपोरेट क्षेत्र के रूप में जाना जाता हैं।

भारतीय व्यवसायिक (Corporate) क्षेत्र काफी बड़े और उच्च विविधता वाले हैं। 1990 के दशक के बाद के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भूमिका कई गुना बढ़ गई हैं।

ग) पेशेवर वर्ग

स्वतंत्र भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने उद्योगों, व्यापार और वाणिज्य, निर्माण, परिवहन, सेवाओं और अन्य विविध आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोले हैं। इसके साथ ही, राज्य ने एक विशाल संस्थागत स्थापना की है जिसमें देश की लंबाई और चौड़ाई में एक जटिल नौकरशाही संरचना शामिल है। इसने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार, चाहे निजी या सरकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, आदि जैसी योग्यता की आवश्यकता हो। नौकरशाह, प्रबधंन अधिकारी, तकनिकीविद, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनके पास इस तरह के कौशल हैं।

घ) छोटे व्यापारी और दुकानदार

ये वर्ग आधुनिक शहरों और कस्बों के विकास के साथ विकसित हुए हैं। वे वस्तुओं और वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बड़े समूह के बीच की कड़ी का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उत्पादकों या थोक विक्रेताओं से सामान खरीदतें है और इसे उपभोक्ताओं के बीच बेचते है। इस प्रकार, वे अपने जीवन की उन कीमतों के लाभ अन्तर पर बनाते हैं, जिस पर वे अपने माल और वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं।

इसमें एक ओर स्व-नियोजित छोटे दुकानदार व्यापारी, विक्रेता, फेरीवाले और दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र में अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल हैं।

च) श्रमिक वर्ग

श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। यह आधुनिक श्रमिक वर्ग था जो ब्रिटिश काल के दौरान भारत में स्थापित आधुनिक उद्योगों, रेलवे और वृक्षारोपण

का प्रत्यक्ष परिणाम था। यह वर्ग भारत में विकसित और विस्तारित होते हुए वृक्षारोपण, कारखानों, खनन, उद्योग, परिवहन, रेलवे और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के अनुपात में बढ़ता गया। भारतीय मजदूर वर्ग का गठन मुख्य रूप से गरीब किसानों और बर्बाद हुए कारीगरों से हुआ था।

7.4 जाति और वर्ग के बीच संबंध

भारत में जाति और वर्ग की प्रकृति से संबंधित बहुत सारे वाद विवाद हैं। कुछ के दृष्टिकोण में जाति और वर्ग एक दूसरे से विपरीत हैं और कुछ के दृष्टिकोण में जाति और वर्ग के बीच संबंध है। आइए पहले चर्चा करें कि जाति और वर्ग एक दूसरे से विपरीत हैं।

पश्चिमी विद्वानों और विशेष रूप से ब्रिटिश प्रशासकों और नृवंशविज्ञानियों ने जाति और वर्ग को एक दूसरे के विपरीत समझा। वे मानते हैं कि जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न रूप हैं। वर्ग प्रणाली में रैंक की गई इकाइयाँ व्यक्ति हैं; और जाति व्यवस्था में स्थान पाने वाले लोग समूह हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जाति से वर्ग, पदानुक्रम से लेकर स्तरीकरण, बंद व्यवस्था से खुली व्यवस्था में और सावयवी खंडात्मक प्रणाली तक में परिवर्तन हो रहा हैं। जाति और वर्ग के बीच ऐसा भेद मानव निर्मित हैं।

जाति और वर्ग का ऐसा दृष्टिकोण इसे कुछ विशेषताओं के आधार पर पदों की वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के परिणामस्वरूप माना जाता है। वर्ग को तरलता के रूप में और जाति को कठोरता के रूप में सामाजिक स्तरीकरण के इन दो प्रणालियों के लिए सोचना बहुत कठिन और अवास्तविक है। जाहिर तौर पर इसका मतलब होगा कि जाति को परिभाषित करने की स्थिति कठोरता और अपरिवर्तनीयता, सावयवी, एकजुटता, कार्यात्मक निर्भरता, होमो पदानुक्रम और अशुद्वता शुद्वता से हैं। वर्ग का वर्णन व्यक्तिवाद, प्रतियोगिता और समानता की विचारधारा द्वारा किया जाता हैं। जाति और वर्ग के ऐसे निर्माण भ्रामक हैं।

सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली के रूप में जाति कठोरता और तरलता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, पवित्रता और व्यक्तिवाद, अन्यान्याश्रय और स्वायत्तता, और असमानता और समानता दोनों का एक प्रतिनिधित्व करती हैं। इन ध्रुवीय चरित्र की उत्पत्ति गैर जाति के पश्चिमी समाज की श्रेष्ठता की धारणा में निहित हैं। जाति और वर्ग के बीच ये भेद ऐतिहासिक और अनुभवात्मक सामग्री पर आधारित होने के बजाय विश्लेषणात्मक हैं।

यह भेद कि जाति एक वास्तविक घटना है और वर्ग एक श्रेणी हैं, एक गुणात्मक निर्माण हैं, अस्थित है। जाति और वर्ग दोनों वास्तविक और अनुभवजन्य हैं। दोनों परस्पर क्रियात्मक और श्रेणीबद्व हैं, और एक दूसरे को शामिल करते हैं। यह गतिशील और विरोधाभास से भरा हुआ हैं। जातिगत मानदंडों का उल्लंघन सामाजिक स्तरीकरण के सिद्वांत के रूप में जाति को हटाने के लिए नहीं करता है। इस प्रकार, जाति वर्ग को शामिल करती है और वर्ग जाति को शामिल करता हैं, न तो ''जाति दृश्य'' और न ही ''वर्ग दृश्य'' भारत की सामाजिक वास्तविकता के संपूर्ण सरगम को समझा सकता हैं। अब भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए जाति वर्ग के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं।

जाति वर्ग संबंध, जाति और वर्ग के अवलोकन को परस्पर निहित घटनाओं के रूप में उपयोग करता हैं। जाति वर्ग की सांठ गांठ एक ढाँचे के रूप में सूक्ष्म लेन देन से आगे जाती है और वैकल्पिक रूप से स्थूल संकल्पनाओं को जमीनी हकीकत तक पहुँचाती है। जाति वर्ग की सांठगांठ का अर्थ है जाति से परे और सामाजिक वास्तविकता की एक दूरी समझ के लिए 'जाति वर्ग से परे' अंतर्यबंध जाना। यह सांठगांठ को एक ''संबंधों का एक

समूह के रूप में परिभाषित करता है जो संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का आधार बन जाता हैं। सांठगांठ का अर्थ जाति और वर्ग में किसी तरह का संवाद या समरूपता नहीं है। सामाजिक संबंधों की परस्पर निर्भरता, विरोधाभास, समरूपता और आधिपत्य संदर्भ के एक फ्रेम के रूप में सांठगांठ की अभिन्न विशेषताएं हैं। आंद्रे बेते ने कहाः ''गाँव में जाति, वर्ग और सत्ता की पदानुक्रम कुछ हद तक अधिव्यापित होती हैं, लेकिन साथ ही कट भी जाती हैं।'' उन्होने यह भी कहा कि सामाजिक जीवन के कई क्षेत्र अब कुछ हद तक 'जाति मुक्त' हो रहे हैं। ब्राह्मण परंपरा के अलावा, मार्शल राजपूत का विचार, भारतीय शिल्पकार की पंरपराएं, भारतीय व्यापारी, और वर्ग और सांस्कृतिक परंपराएं भारतीय समाज में मौजूद थीं।

कैथलीन गॉफ द्वारा एक सामाजिक गठन के रूप में उत्पादन की विधा के विश्लेषण में इस सांठगांठ को भी उजागर किया गया हैं, जिसमें वह एक ओर जाति, रिश्तेदारी, परिवार और विवाह के बीच के संबंध और दूसरी ओर उत्पादन और उत्पादन संबंधो की ताकतों को खोजता हैं। भारत में जाति और रिश्तेदारी के संदर्भ में वर्ग संबंधो को मुख्य धारणा के रूप में लिया जाता हैं। यहां तक कि वर्ण और जजमानी प्रणाली को कुछ विद्वानों द्वारा वर्ग संबंधों और उत्पादन के तरीके के सदर्भ में समझाया गया हैं।

इस प्रकार, जाति और वर्ग काफी हद तक, समान संरचनात्मक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातिगत संघर्ष भी वर्ग संघर्ष हैं क्योंकि उच्च और निम्न जातियां अपने सामाजिक नियोजन के संदर्भ में क्रमशः उच्च और निम्र वर्गों से मेल खाती हैं। जातियां वर्ग के रूप में भी कार्य करती हैं क्योंकि वे हित समूहों के रूप में कार्य करती हैं। जाति संघ अपने सदस्यों के लिए कई आर्थिक और राजनीतिक गतिविधयाँ करते हैं।

7.5 सारांश

इस इकाई में हमने एक संस्था के रूप में जाति और वर्ग का वर्णन किया हैं। हमने वर्णन किया है कि परिवर्तन हमेशा जाति व्यवस्था का हिस्सा रहा है। जाति का लचीलापन और समायोजन प्रकृति आवश्यक पहुलुओं में से एक हैं, जिसमें इसकी निरंतरता को बनाए रखा हैं। हमने भारत में वर्गों के विकास को भी रेखांकित किया है। हमने जाति और वर्ग के बीच संबंधों पर चर्चा की हैं।

7.6 संदर्भ

दास, अरंविद और सीता देउलकर (2002) कास्ट सिस्टमः ए होलिस्टिक व्यु। डोमिनैंट पब्लिशरः नई दिल्ली.

मैनडेलबौम, डेविड जी (1972) सोसाइटी इन इंडिया। पोप्युलर प्रकाशनः बॉम्बें.

शर्मा, के.एल. (1998) कास्ट, फ्युडलिस्म एंड पीजैन्टरी : द सोशल फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः नई दिल्ली.

श्रीनिवास, एम एन (सं) (1960) इंडिया विल्लैजेस। एशिया पब्लिषिंग हाउसः बॉम्बे

श्रीनिवास, एम एन (1961) द डॉमिनेंट कास्ट एंड अदर एस्सैज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : नई दिल्ली

श्री निवास एम एन (1962) कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्सैत, एशिया पब्लिशिंग हाउसः बॉम्बे

श्रीनिवास, एम एन (सं) (1996) कास्ट, इट्स ट्वेन्टींएथ सेंचुरी अवतार, पेंगुइन बुक्सः नई दिल्ली

बेली, एफ. जी (1957) कास्ट एंड द इकोनोमिक फ्रंटियर, द यूनिवर्सिटी प्रेस : मैनचेस्टर.

बैते, ए (1966) कास्ट, क्लास एंड पावर : चेंजिग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ए तनजोर विल्लेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः बॉम्बे

बैते, ए (2000) द क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाईम, पेंगुइन बुक्सः नई दिल्ली

कोठारी, आर (1970), कास्ट इन इंडियन पोलिटिक्स, ओरिएंट लॉन्गमैन : नई दिल्ली

रूडोल्फ (L.I.) और (S.H.) रूडोल्फ (1967), द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पोलिटिकल डेवलप्मेंट इन इंडिया, द यूनिवर्सिटी आफॅ षिकागो प्रेस, षिकागो

बैते, ए (1974) स्टडीज़ इन इंडिया एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ओ यू पीः दिल्ली

बैते, ए (1967) द फ्यूचर आफॅ द बैकवर्ड क्लास्सेजः कम्पीटिंग डिमांड्स ऑफ स्टेटस एंव पावर। इन फिलिप मेसन (सं), इंडिया एंड सीलोनः युनिटी एंड डाईवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः लंदन, पष सं 83-120

बैते, ए (1985) द बैकवर्ड क्लासेस एंड द न्यू सोशल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः दिल्ली

बैते, ए (1992) द बैकवर्ड क्लास्सेज इन कन्टेम्पेररी इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः नई दिल्ली

देसाई, ए. आर. (1987) सोशल बैकग्राउंड आफॅ इन्डियन नेशनलिस्म, पॉपुलर प्रकाशनः बॉम्बे, अध्याय III-XI

शर्मा, के एल (1997), सोशल स्ट्रेफिकेशन एंड मोबिलिटी रावत पब्लिकेशन, जयपुर.

सिंह, योगेन्द्र (1977), मॉडर्नाईजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, थॉमसन प्रेसः फरीदाबाद अध्याय V

सिंह, योगेन्द्र (1988), सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, मनोहरः दिल्ली पष सं 1-90.

सिंह, योगेन्द्र (2000) कल्चर चेंजेस इन इंडियाः आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाईजेशन, रावत पब्लिकेशंसः जयपुर।

7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्नों के उत्तर 1

i) जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप हैं, जो समाज को विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करता हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अनुष्ठान शुद्वता और अशुद्वता के मानदंडों पर एक श्रेणीबद्व क्रम में रखा गया हैं। यह वंशानुगत और अन्तर्विवाही है। इसके पास एक पारंपरिक संगठन हैं, जो एक व्यवसाय के साथ है और अधिकतम समानता का निरीक्षण करता हैं।

ii) जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं

   क) पदानुक्रम

   ख) सगोत्र विवाह

ग) एक वंशानुगत व्यवसाय के साथ संबंध।

घ) उत्तरदायी

च) शुद्वता, अशुद्वता

छ) वर्ग

ज) जाति

बोध प्रश्नों के उत्तर 2

i) सामाजिक वर्ग एक प्रकार का सामाजिक समूह हैं, जिसे न तो कानूनी रूप से परिभाषित किया जाता है और न ही धार्मिक रूप से मंजूरी दी जाती है। इसे ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभषित किया गया है जो समाज में एक समान स्थिति साझा करते हैं। वे अपेक्षाकृत खुले हैं और कोई भी व्यक्ति जो धन के बुनियादी मानदंडों और जीवन की संबद्व शैली आदि को संतुष्ट करता हैं, वह इसका सदस्य बन सकताक है। किसी समाज में सामाजिक वर्गों को मुख्य रूप से धन और आय के आधार पर श्रेणीबद्व रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वर्ग औद्योगिक समाजों की विशेषता हैं।

ii) भारत में सामाजिक वर्गों के उदय के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं (क) बदलती भूमि प्रणाली, (ख) व्यापार और वाणिज्य, (ग) औद्योगिकीकरण, (घ) राज्य और प्रशासनिक प्रणाली, और (च) आधुनिक शिक्षा।

iii) सामाजिक वर्गों की असमान वषद्वि दो क्षेत्रों में हुई। एक भारत के विभिन्न हिस्सों में और दूसरा, भारत के विभिन्न समुदायों में था।